भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 855

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

855 श्री संजय कुमार झा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ख) मंत्रालय द्वारा भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हुए एफटीए की पृष्ठभूमि में, वर्ष 2026 से वर्ष 2030 की अवधि में, दोनों देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के कुल परिमाण (अमेरिकी डॉलर में) के संबंध में किए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी पंद्रह वर्षों की अवधि में न्यूज़ीलैंड द्वारा किए जाने वाले 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से किन भारतीय राज्यों के लाभ प्राप्त करने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत-न्यूजीलैंड एफटीए में, भारत ने न्यूजीलैंड को अपनी 70.03% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतों का प्रस्ताव किया है। शेष 29.97% टैरिफ लाइनों को बहिष्करण सूची में रखा गया है, और भारत की बहिष्करण सूची में मुख्य रूप से वे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें घरेलू दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। प्रमुख बहिष्करण उत्पाद निम्नवत हैं:

- दुग्ध उत्पाद (दूध, क्रीम, मट्ठा, दही, पनीर आदि)
- पशु उत्पाद (भेड़ के मांस के अलावा)
- वनस्पति उत्पाद जैसे प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम आदि
- चीनी और चीनी से बनी मिठाइयाँ
- पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवों से प्राप्त वसा और तेल
- हथियार और गोला-बारूद

• रत्न और आभूषण (कीमती धातुएँ और तैयार आभूषण)
• तांबा और तांबे की वस्तुएँ (कैथोड, कारतूस, छड़ें, बार, कॉइल आदि)
• एल्युमीनियम और एल्युमीनियम की वस्तुएँ (पिंड, बिलेट, तार की छड़ें)

(ख) भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (आईएन-एनजेड एफटीए) संवर्धित बाजार पहुंच, व्यापार संबंधी बाधाओं में कमी और संवर्धित नियामक संबंधी सहयोग के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार को सुगम बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस समझौते का उद्देश्य न्यूजीलैंड बाजार में भारतीय वस्तुओं को नि:शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करके मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देना है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की वास्तविक मात्रा वैश्विक आर्थिक स्थितियों, बाजार की गतिशीलता, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और वाणिज्यिक विचारों सहित कई कारकों पर निर्भर करेगी।

(ग) 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आने से भारतीय व्यवसायों को मदद करेगा और सभी राज्यों में निवेश को सुगम बनाएगा, जिससे देश के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

*****